

अब आ गए गाँधीजी के दिन

डॉ. सुजीत सिन्हा

एक सौ ग्यारह साल पहले, सन 1909 में “हिन्द स्वराज” के छठे अध्याय “सभ्यता” में गाँधीजी ने लिखा था “ये आधुनिक सभ्यता तो ऐसी है कि जरा धीरज धरो तो खुद ही इसका विनाश हो जाएगा”।

आज से पचहत्तर साल पहले 5 अक्टूबर, 1945 को गाँधीजी ने नेहरू को चिट्ठी में लिखा “मुझे इस बात से डरना नहीं चाहिए कि दुनिया आज उल्टी तरफ जा रही है। ये हो सकता है कि भारत भी उसी तरफ जाएगा और उस पतंगे की तरह मर जाएगा जो आग में जलकर राख होने के पहले आग के चारों ओर तेज़ी से नाचने लगता है।”

उद्योगवाद का अंत

आज सन 2021 में उद्योगवाद का पतंगा पागल की तरह झूमते हुए आग में गिरने ही वाला है। जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखने वाला अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल (IPCC) कह रहा है कि बस दस ही साल बाकी हैं।¹ क्योंकि पृथ्वी की विशेष प्राकृतिक सीमाओं (Planetary boundaries) को लाँघा जा चुका है। प्राकृतिक विनाश और जलवायु के आपातकाल (साइक्लोन, बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी और ठंड की लहर) तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोरोना (COVID 19) ने पूरी दुनिया को नचा दिया है। इनके पीछे जल्दी ही आ रही है परमाणु अघटन (अस्त्र, और भी कई चर्नोबिल, फुकुशिमा), रासायनिक अघटन (हजारों भोपाल गैस काण्ड जैसे हादसे), जैविक दुर्घटनाएं (जैविक हथियार, जेनेटिक रूपांतरित जीव, कोरोना जैसे और भी महामारी, पशु पालन कारखानों से अघटन), मनुष्य जनित भूकम्प, गिरते हुए बड़े बाँध, आर्थिक निपात, बढ़ती असमानता, बेकारी, प्रवास, शरणार्थी, हर स्तर पर संसाधनों के लिए भयानक संघर्ष, हथियारों की दौड़, बढ़ती असहनशीलता (धर्म, वर्ण, जाति, भाषा), राष्ट्र और कंपनी स्तर पर बढ़ती फ़ासीवाद और अधिनायकवाद।

चलिये अब जरा कल्पना करते हैं कि यदि हमें CO₂ का उत्सर्जन तेज़ी से घटाना है तो किन-किन चीजों का बहुत ज़ल्द ही पर्याय ढूँढ़ना होगा। क्या-क्या उद्योगवाद के साथ-साथ खत्म हो जाएगा और इस उद्योगवाद के पतन के साथ या उसके बाद हमारा जीवन कैसा रहेगा? कल्पना करते-करते आप स्वयं ही देखेंगे कि जो छवि उभर कर आती है, वह एकदम गाँधीवादी छवि है! और ऐसा लगता है कि मानो आज के युग में एक बार फिर से गाँधीजी ने एक सादगी, समता और सद्भावना का जीवन जीने के लिए एक घोषणा पत्र लिखा है!

1 <https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/>

2 <https://www.weforum.org/agenda/2020/07/climate-change-increased-carbon-dioxide-emissions-scientists/>

आइये, कल्पना करते हैं कि :

1. **जीवाश्म ईंधन - कोयला, पेट्रोलियम का उपयोग** बहुत कम करना होगा। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाएँगे; और भी आविष्कार हो सकते हैं। परन्तु यदि हमें अगले दस सालों में पृथ्वी को नष्ट होने से बचाना है तो आज की तुलना में इन साधनों का बहुत कम इस्तेमाल करना होगा।
2. **पृथ्वी का कुल औद्योगिक उत्पादन** बड़ी मात्रा में घटेगा। कच्चे माल का निष्कर्षण और उसका विश्वव्यापी वितरण - ये सब पूरी तरह ईंधन पर निर्भरशील हैं। इसी कारण बड़े पैमाने पर इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा जैसे 30-40 धातु, प्लास्टिक, सिलिका, सीमेंट, काँच इन सबका उत्पादन घट जाएगा।
3. **कृषि में रसायनों का प्रयोग** करना संभव नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन की जो प्राकृतिक चक्र की सीमा है, उसका उल्लंघन हो चुका है।
4. **विश्व भर में बाज़ारीकरण** जल्दी से घट जाएगा; यहाँ तक कि एक देश के भीतर भी बहुत मात्रा में सामान दूर नहीं जा पाएगा।
5. **प्राइवेट मोटर गाड़ी** एक तरीके से उद्योगवाद की प्रतीक हैं - यह सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देने वाली वस्तु है - जो बंद हो जाएँगे, वह चाहे पेट्रोलियम या बैटरी (वो भी ईंधन से ही आती हैं) चालित हों।
6. **विशाल यातायात व्यवस्था** अर्थनीति के संकुचित होने के कारण आदमी और वस्तुओं ले लिए - रास्ता, रेल, समुंद्र, हवाई जहाज से इतने आने-जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। यहाँ तक कि काम के लिए दैनंदिन 10-15 किलोमीटर से अधिक जाना भी बंद हो जाएगा।
7. **पृथ्वी की सबसे बड़ी लगभग एक लाख प्राइवेट या सरकारी कंपनियाँ** 99 प्रतिशत गायब हो जाएंगी क्योंकि अब एक अलग अर्थनीति में उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी।
8. **राष्ट्र** का आधुनिक रूप में जन्म उद्योगवाद के साथ-साथ ही हुआ है। आधुनिक राष्ट्र का मुख्य कार्य है उद्योगवाद की अर्थनीति और टेक्नोलॉजी का समन्वय करना। अगर उद्योगवाद नहीं, तो राष्ट्र की भी कोई ज़रूरत नहीं। पर्यावरण में यदि कार्बन का स्तर घटाने के लिए हम बड़े यातायात को सीमित करें तो बड़े स्तर की भूमंडलीकृत अर्थनीति की आवश्यकता कम होगी। इस अर्थनीति को चलाने के लिए जो राजनीति अभी हमारे सामने है उसकी भी ज़रूरत कम हो जाएगी।
रोटी-कपड़ा-मकान-बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, राशन, बालवाड़ी, नरेगा- छोटे स्तर पर विभिन्न समुदाय अपनी-अपनी ज़रूरत समझते हुए अपने अनुसार नीति बनाएँगे। अगर ऐसा करने लगेंगे तो राष्ट्रवादी केंद्रीयकृत नीति की आवश्यकता नहीं रहेगी और इन नीतियों को बनाने और संभालने के लिए जो भारी भरकम राष्ट्र सरकार चाहिए- उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। “राष्ट्र और नीति” ये दो शब्द ही गायब हो जाएँगे, उदाहरण के लिए “राष्ट्रीय शिक्षा नीति”!!!
9. **पार्लियामेंट और चुनाव प्रतिनिधि वाला गणतंत्र** भी अपना स्वरूप बदल देगा। यदि राष्ट्र शक्तिहीन होते जाएँगे तो इस तरह के चुनावों के स्थान पर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर होंगे।
10. **उद्योगवाद से जुड़ा हुआ उत्पादन, उससे जुड़े हुए सेवामूलक काम**, उद्योगवाद के विशाल राष्ट्र सरकार की नोकरियाँ- ये सब उद्योगवाद के पतन के साथ खत्म हो जाएँगे।
11. **बड़े शहर** संकुचित हो जाएँगे। क्योंकि बड़े शहरों में उद्योगवाद से जुड़ा कोई काम ही नहीं रहेगा। करोड़ों की जनसंख्या के शहर को खाद्य पदार्थ पहुँचाने के लिए जिस व्यवस्था की ज़रूरत होती है वह अब उद्योगवाद के पतन के साथ संभव नहीं होगी।

12. राष्ट्र और दुनिया भर की मुद्रा व बैंक व्यवस्था बहुत संकुचित हो जाएगी और विश्व की मुद्रा की भी ज़रूरत घट जाएगी क्योंकि ज़्यादातर सामग्री इनके माध्यम से क्रय-विक्रय नहीं की जाएगी।

13. उद्योगवाद यदि खत्म तो स्कूल नामक संस्था की भी और ज़रूरत नहीं रहेगी। पूरे देश में एक समान करिकुलम, सर्टिफिकेट वाले शिक्षक, “बोर्ड” परीक्षा, सरकारी प्रमाणपत्र - ये सब कोई काम के नहीं रहेंगे।

14. पृथ्वी की 99 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थाएं (सरकारी या प्राइवेट) बंद हो जाएंगी। नए तरीके के समाज के लिए आज की उच्च शिक्षा की संस्थाओं की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी।

आज के लिए गाँधीजी का विकल्प

अगर इस तरीके से उद्योगवाद के विनाश या पतन के बाद की दुनिया की उपरोक्त कल्पना की जाए तो इसकी कुछ ऐसी तस्वीर उभरती है :

ज़्यादातर लोगों के रहने और काम करने की जगह होगा छोटा गाँव और छोटा शहर। खेती, पशुपालन, जंगल, हस्तशिल्प, स्थानीय सेवाएं, व्यापार, सभी में समवाय प्रक्रिया से काम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इकोलॉजी की नीतियों को अपनाने की सतत चेष्टा रहेगी। जीवाश्म ईंधन, धातुओं और प्रकृतिनाशक वस्तुओं के प्रयोग को कम करते हुए, स्थानीय वस्तुओं का उचित प्रयोग होगा। सभी संपत्ति और संसाधन पूरे समुदाय के होंगे, किसी एक-दो परिवार के नहीं। स्वदेशी नीति को मानते हुए 90 प्रतिशत उत्पादन का भोग 10-12 किलोमीटर के अंदर होगा। दूर के बाजार में बहुत कम चीजें जाएंगी और आएंगी। गाँव और मोहल्ले की आम सभा में आमने-सामने लोकतंत्र के द्वारा सब निर्णय होगा। इसमें 12 साल के ऊपर के बच्चे भी भाग लेंगे। समुदाय के लगातार सत्याग्रह के माध्यम से सभी प्रकार की विषमताएं- नारी, पुरुष, धर्म, जाति, वर्ण, भाषा कम होती रहेंगी। लोग सामुदायिक रसोई घर में एक साथ खाना बनाएंगे और खाएंगे। बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरे समुदाय की होगी, किसी एक परिवार की नहीं। 5-10-20-100-200 समुदाय लेकर शासन स्तर बनेंगे; पर ये सभी स्तरों में कोई क्षमता की ऊँचाई नहीं होगी। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो समुदाय स्तर की ही होंगी। राष्ट्र, राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रवाद ऊब जाएंगे।

संक्षेप में राष्ट्रीय उद्योगवाद का विकल्प होगा- न्याय और समतापूर्ण, मितव्ययी और समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल, शान्तिपूर्ण और सृजनशील, प्रेम भाईचारा से भरा, स्वयं संपूर्ण, स्वयं शासित, प्रकृति बंधु, छोटे ग्रामीण और शहरी समुदाय।

शिक्षा की चुनौती

ऐसे आदर्श समाज के लिए चाहिए आज की नई - ‘नई तालीम’। पहले तो, गाँधीजी के अनुसार, ऐसी शिक्षा हर एक को स्वराज दिलाने में सक्षम होगी। स्वराज यानि अपने पर राज के जितने भी कौशल हैं वो बचपन से ही सिखाये जाएंगे और जिसे यह स्वराज प्राप्त होगा वो दूसरों के साथ मिलकर उद्योगवाद से संघर्ष करेगा; और साथ ही हरेक दिशा में- आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक, राजनैतिक विकल्प के निर्माण का काम करेगा।

इसके साथ ऐसी शिक्षा स्थानीय भाषा में स्थानीय शिक्षक को लेकर होगी। आध्यात्मिक बोध, पूरी मानव जाति, पूरी पृथ्वी और प्रकृति के साथ एकात्म बोध- ये शिक्षा का अभिन्न अंग होगा। कोई राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय या विभाग नहीं रहेगा जो शिक्षक नियुक्त करना, उनको तंख्वाह देना, पाठ्यक्रम बनाना, किताबे लिख कर छापना, बोर्ड की परीक्षा लेना, सर्टिफिकेट देना इत्यादि ये सब काम करेगा। समुदाय की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक कार्यक्षेत्र, उसका प्राकृतिक वातावरण- ये ही होंगी शिक्षित होने की जगह। केवल कोई अलग से बना स्कूल या कक्षा-कक्ष नहीं। समुदाय का जीवन चक्र और वहाँ की जलवायु से शिक्षा का समय काल निर्धारित होगा। अपने समुदाय और स्थानीय समस्याओं का हल करना शिक्षा का पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम हर एक स्थान के लिए अलग-अलग होगा। अपनी और स्थानीय इतिहास से बात शुरू होगी। परन्तु पूरी दुनिया के इतिहास से संपर्क के बारे में सीखेंगे।

और क्या नहीं होगा? ये बच्चे और उसके परिवार के आर्थिक सीढ़ी में उठने की आकांक्षा पूरी करने की शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि ऐसी कोई सीढ़ी ही नहीं रहेगी। हर काम की समान मर्यादा और समान वेतन वाला समाज होगा। यह गाँव और छोटा शहर छोड़कर बड़े शहर में जाने की भी शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि बड़े शहर ही नहीं रहेंगे।

इस दिशा में जो विभिन्न प्रयोग किये जा रहे हैं उनका इस अंक में विवरण है। उससे यही आशा है कि वह हम सभी लोगों को प्रेरित करें। यही है आज की हमारी चुनौती। क्योंकि उद्योगवाद का सूरज ढल चुका है। समय कम है और गाँधीजी के स्वराज की ओर जाने का रास्ता हमारे सामने है। ◆

लेखक परिचय : देहरादून और असम से स्कूली शिक्षा, कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से रसायन में बी.एस.सी., आई.आई.टी.कानपुर से एम.एस.सी., अमरीका की प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी से पी.एच.डी.। एक साल अरुणाचल प्रदेश के स्कूल में शिक्षण, दो साल अमरीका में बेल लैब्स में रिसर्च, 20 साल बंगाल के गाँव में विकास का काम और दस साल अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में शिक्षण। आजकल उद्योगवाद के विकल्प की कहानियाँ सुनाते हैं।

संपर्क : sujit.sinha@apu.edu.in